**भारत सरकार**
**वित्त मंत्रालय**
**आर्थिक कार्य विभाग**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 1103**

**(**जिसका उत्तर सोमवार दिनांक **10** फरवरी**, 2025/21** माघ**, 1946 (**शक) को दिया जाना है)

**प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को आकर्षित करने वाले प्रमुख क्षेत्र**

**1103. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही**:

क्या वित्त **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

**(**क) क्या सरकार ने आने वाले वर्षों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को आकर्षित करने वाले प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है**;**

**(**ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों का विवरण और एफडीआई प्रवाह बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध विशिष्ट उपाय क्या हैं**;**

**(**ग) विकास क्षेत्र में एफडीआई बढ़ाने में ईज-ऑफ-डूइंग-बिजनेस (ईओडीबी) सुधारों की भूमिका कितनी है**;** और

**(**घ) रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास और आर्थिक विकास पर इन पहलों का अनुमानित प्रभाव क्या पड़ेगा**?**

**उत्तर**
**वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)**

(क) और (ख): अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित करने के लिए, सरकार ने निवेशक अनुकूल एफडीआई नीति लागू की है, जिसके तहत कुछ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्र ऑटोमेटिक रूट के तहत 100% एफडीआई के लिए खुले हैं। सरकार ने रक्षा, पेंशन, अन्य वित्तीय सेवाएं, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां, प्रसारण, फार्मास्यूटिकल्स, एकल ब्रांड खुदरा व्यापार, निर्माण और विकास, नागर विमानन, पावर एक्सचेंज, ई-कॉमर्स गतिविधियां, कोयला खनन, संविदा विनिर्माण, डिजिटल मीडिया, बीमा मध्यस्थ, बीमा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा दूरसंचार इत्यादि जैसे क्षेत्रों में कई परिवर्तनकारी एफडीआई सुधारों को लागू किया है। इसके अलावा, सरकार एफडीआई नीति की निरंतर आधार पर समीक्षा करती है और समय-समय पर महत्वपूर्ण बदलाव करती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत एक आकर्षक और निवेशक अनुकूल केंद्र बना रहे।

(ग) और (घ): ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) प्रवेश बाधाओं को कम करके, विनियमों को सुव्यवस्थित करके और पारदर्शिता सुनिश्चित करके एफडीआई को आकर्षित करता है। व्यापार स्थापना, कराधान और कानूनी सुरक्षा के लिए प्रभावी प्रक्रियाएं निवेशकों का विश्वास बढ़ाती हैं, जिससे देश अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनता है। ईओडीबी और उदारीकृत एफडीआई नीतियां अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक, स्थायी पूंजी को आकर्षित करती हैं, प्रौद्योगिकी अंतरण को बढ़ावा देती हैं, कार्यनीतिक क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहित करती हैं और नवाचार, प्रतिस्पर्धा तथा अधिक रोजगार सृजन को बढ़ावा देती हैं। भारत सरकार का लक्ष्य घरेलू पूंजी, प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता को संपूरित करने हेतु एफडीआई को आकर्षित करना और प्रोत्साहित करना है, जिससे त्वरित आर्थिक वृद्धि और विकास उत्प्रेरित होता है।

*****